निजी स्कूलों ने 59 फीसदी तक बढ़ाई फीस, पैरंट्स क्या आत्महत्या कर लें

फरीदाबाद के हजारों अभिभावकों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को पत्र लिखे, ट्वीट किए, कोई सुनवाई नहीं

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: शहर के निजी स्कूलों ने नए शिक्षा सत्र के लिए 59 से 60 फीसदी तक फीस बढ़ा दी है। हजारों बच्चों के माता-पिता ने इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से सीधी शिकायत की है। कुछ ने तो पीएम मोदी तक को निजी स्कूलों की लूट के बारे में लिखा है, लेकिन कहीं से

कोई राहत नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ कुछ स्कूलों में छह-छह महीने से स्कूलों ने अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन तक नहीं दिया है। वेतन मांगने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।

मनमानी की सीमाएं टूटीं

फीस बढ़ोतरी के मामले में फरीदाबाद के डीएवी स्कूल 14 समेत उसकी सभी शाखाएं, आयशर पब्लिक स्कूल, मॉडर्न डीपीएस, सेंट कोलम्बस, अरावली इंटरनैशनल, एमवीएन स्कूल, डीपीएस, एपीजे आदि ने बिना सोचे समझे फीस बढ़ोतरी कर दी है।

डीएवी स्कूल सेक्टर 14 में 12वीं में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता ने बताया कि स्कूल कुल तीन घंटे की आनलाइन क्लास चला रहा है और बच्चे की फीस उसी तरह मांगी गई है, जैसे स्कूल खुला होने पर ली जाती है। बच्चे के पिता से फौरन 20,520 रुपये अप्रैल, मई, जून की फीस जमा कराने को कहा गया है, जबकि पिछले साल इसी स्कूल ने इसी बच्चे की इसी तीन महीने की फीस 12,900 रुपये लिए थे। इस तरह डीएवी ने 12वीं के हर बच्चे की फीस में 59.7 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। यह सिर्फ एक क्लास और एक बच्चे की फीस का मामला नहीं है। हर क्लास की फीस में इसी तरह की बढ़ोतरी की गई है। जिस बच्चे के पिता ने यह जानकारी दी है, वो एक मल्टीनैशनल कंपनी में लीगल अफसर हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल का स्टाफ पैरंट्स को फोन पर फीस जमा कराने को कह रहा है, जमा न कराने पर बच्चे का नाम आनलाइन क्लास से काटने की धमकी दी जा रही है।

आयशर स्कूल ने पिछले साल हर महीने की जहां सिर्फ ट्यूशन फीस ली थी, इस बार ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी के साथ-साथ एक्टिविटी चार्ज 1081 रुपये, वार्षिक शुल्क 1500 रुपये और ट्यूशन फीस 5900 रुपये ले रहा है। जबकि पिछले साल आयशर स्कूल ने इसी बच्चे के अभिभावक से सिर्फ ट्यूशन फीस के हर महीने 5080 रुपये लिए थे। अगर तुलना करें तो ट्यूशन फीस में ही करीब एक हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह एक बच्चे की फीस का डिटेल है।जिन पैरंट्स के तीन बच्चे अगर इस स्कूल में पढ़ रहे हों तो उनका क्या हाल हो रहा होगा।

मॉडर्न डीपीएस में पढ़ने वाली याशना सागर की आनलाइन क्लास स्कूल ने अचानक बंद कर दी। उसके पैरंट्स बढ़ी हुई फीस नहीं दे पाए थे। बेटी डिप्रेशन का शिकार हो गई। उसके पिता भारत भूषण सागर ने फौरन सीएम और गृह मंत्री अनिल विज को लिखा। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। जो वो स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गए तो उसने बदतमीजी की और कहा कि सरकार या उसका शिक्षा विभाग हमारा स्कूल नहीं चलाता। हम फीस अपने हिसाब से ही लेंगे। बेटी को पढ़ाना है तो पढ़ाओ, वरना अपना रास्ता देखो। एक अभिभावक ने दुखी मन से कहा कि क्या हम बच्चों की पढ़ाई के लिए आत्महत्या कर लें तभी खट्टर सरकार कुछ ध्यान देगी।

बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि इस साल तो कोरोना पिछले साल से भी ज्यादा भयानक था। कितने घरों में मौतें हो चुकी हैं, कितनों की नौकरियां छूट चुकी हैं, कितनों की सैलरी आधी हो चुकी है लेकिन स्कूल पैरंट्स पर रहम करने को तैयार नहीं हैं। आनलाइन क्लास में स्कूलों का बिजली-पानी तो बच ही रहा है, उनके किसी इन्फ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल बच्चे नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद फीस बढ़ोतरी का कोई उचित कारण इन स्कूलों के पास नहीं है। तमाम स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर बच्चों के मां-पिता से शिकायतें कर रहे हैं कि स्कूल वालों ने उनकी सैलरी कम कर दी है। किसी स्कूल में तीन महीने तो किसी स्कूल में छह-छह महीने से टीचरों को वेतन ही नहीं मिला है। निजी स्कूलों के टीचरों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाई लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। अभिभावक कह रहे हैं कि एक तरह से टीचरों को वेतन देने के नाम पर अभिभावकों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जबकि टीचरों को सैलरी नहीं दी जा रही है। इसका असर आनलाइन क्लास पर पड़ रहा है। बीएन पब्लिक स्कूल में वहां की मैनेजमेंट ने बहुत सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। वहां छह महीने से किसी को सैलरी नहीं दी जा रही थी। जब सैलरी मांगी गई तो स्कूल ने यह कदम उठाया। स्टाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है लेकिन स्कूल से किसी सरकारी एजेंसी ने पूछताछ नहीं की।

स्कूलों का गोरखधंधा, सरेआम लूट

एक आरटीआई के जरिए सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड के उन सभी प्राइवेट स्कूलों की सूची मांगी गई थी, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में बैलेंसशीट के साथ फॉर्म 6 जमा कराया है। जवाब में जानकारी दी गई कि निर्धारित अवधि 31 मार्च 2021 तक सीबीएसई के 150 स्कूलों में से सिर्फ 88 ने फॉर्म 6 जमा कराया है जिसमें से 44 ने बैलेंसशीट नहीं लगाई है। हरियाणा बोर्ड के 350 स्कूलों में से सिर्फ 20 स्कूलों ने फॉर्म 6 जमा कराया है उसमें से भी 10 ने बैलेंसशीट नहीं लगाई है। बैलेंसशीट और फॉर्म 6 से स्कूलों की वास्तविक आमदनी और खर्च का पता चलता है।

फरीदाबाद में डीएवी 14, 37 व बल्लभगढ़, टैगोर, सेंट एंथोनी, एमवीएन 17 व अरावली, एपीजे, मॉडर्न डीपीएस, होली चाइल्ड, एडी स्कूल, अग्रवाल स्कूल बल्लगढ़, डीपीएस 19, 81 व बल्लभगढ़, सेंटथॉमस, तक्षशिला, आयशर, मानव रचना, मॉर्डन स्कूल सेक्टर 17 आदि का आधी अधूरी बैलेंसशीट के साथ फॉर्म 6 प्राप्त हुआ है।

शेष स्कूल ग्रैंड कोलंबस, डीएवी 49 व एनआईटी 3, अग्रवाल 3, रेयान, श्रीराम, फरीदाबाद मॉडल स्कूल, हरमनमाइनर एसओएस, विद्यासंस्कार, गोल्ड फील्ड 16 ने फॉर्म 6 व बैलेंसशीट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा ही नहीं कराई है।

तमाम स्कूलों की बैलेंसशीट की जांच पड़ताल एक सीए ने की। सीए की जांच से पता चला है कि स्कूल प्रबंधकों ने मामूली आमदनी दिखाई है। ट्यूशन फीस के अलावा जिन गैर कानूनी फंड के जरिए फीस वसूली गई है, उन फंड के नाम और उनमें वसूली गई फीस का जिक्र नहीं किया गया है। इसी प्रकार खर्चों में कई फालतू मद जैसे विज्ञापन, लीगल, वार्षिक कार्यक्रम, किताब, कॉपी बेचने, वेलफेयर मनोरंजन, डोनेशन, दिवाली खर्चा, टूर एंड ट्रैवल, प्लॉट व जमीन खरीदने आदि पर लाखों का खर्चा दिखाया है। यह सब पूरी तरह से गैरकानूनी है।

इसके अलावा आमदनी व खर्चा बराबर करने के लिए जो पैसा लाखों में लाभ के रूप में बचा उसे अन्य खर्चों पर दिखा दिया गया है। यह बात भी पकड़ में आई है कि लाभ के पैसे को अपने अन्य संस्थानों में ट्रांसफर किया गया है। जितने अध्यापक व कर्मचारियों के नाम व उनको दी गई सैलरी दिखाई है, उसमें भी हेराफेरी की गई है। बिना कार्यरत अध्यापक व कर्मचारियों के नाम दर्शाए गए हैं। जितना वेतन उनके नाम के आगे दिखाया गया है, असलियत में वह उन्हें दिया ही नहीं गया है। स्कूल प्रबंधकों ने टीचरों से हस्ताक्षर पूरे वेतन पर कराये हैं जबकि आधी सैलरी दी गई है।

स्कूल की शिक्षण सोसायटी के चेयरमैन, एमडी, प्रबंधक व उनकी पत्नी आदि ने हर महीने 5 लाख से ज्यादा वेतन लिया है जबकि वे स्कूल से कोई भी पैसा लेने के हकदार नहीं होते हैं।

जब नेता चाहेगा, तब मिलेगा शहर को पानी

क्यों टूट रही है रैनीवेल की पाइपलाइन, जांच कराओ

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद : नगर निगम फ़रीदाबाद के जल तंत्र पर नेता, भ्रष्ट पार्षद, इंजीनियर और पानी सप्लायर माफिया का क़ब्ज़ा हो गया है। शहर इस समय पानी की भारी क़िल्लत से जूझ रहा है। तमाम इलाक़ों में पिछले 3 दिनों से पानी की एक बूँद भी नहीं नसीब हो रही है।

कौन तोड़ देता है पाइपलाइन?

शहर को पानी यमुना के किनारे बने रैनीवेल से सप्लाई किया जाता है। लेकिन पिछले एक महीने से किसी न किसी पाइपलाइन के टूटने की सूचना आती है। पिछले बीस दिनों

में अभी तक 12 बार पाइपलाइन टूटने की सूचना आती है। ऐसा लगता है कि शहर में जल संकट बनाए रखने के लिए इन पाइपलाइनों को कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर तोड़ देते हैं ताकि शहर में उनकी पानी की बोतलें बिकती रहें।

भाजपा के कई पार्षद टैंकरों से पानी बेचने का धंधा करते हैं. कुछ भाजपा नेताओं ने आरओ प्लांट लगा रखे हैं, जहां से बोतलें सप्लाई होती हैं। कुछ नेता और पार्षद नहर और ट्यूबवेलों से पानी की चोरी तक करते हैं। इस तरह एक पूरा भ्रष्ट सिस्टम फ़रीदाबाद के पानी को कंट्रोल कर रहा है।

रैनीवेल से जो पानी बूस्टर तक आता है और फिर वहाँ से शहर को सप्लाई होता है, आखिर क्या वजह है कि बूस्टरों पर पार्षद क्यों बैठे रहते हैं। हाल ही में एक पार्षद सुरेंद्र अग्रवाल को एमसीएफ के जेई के साथ शराब के जाम कथित तौर पर टकराते पाया गया। हालाँकि पार्षद ने इस आरोप से इनकार कर दिया। यह मान भी लिया जाए कि वो पार्षद एमसीएफ जेई के साथ पानी नहीं पी रहा था लेकिन आख़िर बूस्टर पर एक पार्षद क्या कर रहा था? क्या बूस्टर से भी पानी की चोरी कराई जाती है? कमिश्नर क्यों नहीं इस संवेदनशील मामले की जाँच करा रही हैं?

नगर निगम के दफ़्तरों में बैठे इंजीनियर अपने एसी कमरों से निकलने को तैयार नहीं हैं। चीफ़ इंजीनियर हर वक्त या तो ठेकेदारों की फ़ाइल निपटाता है या फ़ोन पर गप्प मारता रहता है। उसके मातहत सहायक इंजीनियर और जेई उसकी सुनते ही नहीं हैं।

राजनीतिक लाभ

पानी के इस संकट का राजनीतिक फ़ायदा उठाया जा रहा है। कई आरडब्ल्यूए अपनी चमचागीरी में अपने वाट्सऐप ग्रुप पर संदेश डाल रहे हैं कि पानी संकट से निपटने के लिए सीनियर डिप्टी मेयर देवेन्द्र चौधरी जीजान से जुटे पड़े हैं। किसी ग्रुप में उस इलाक़े के भाजपा पार्षद का फ़ोटो डालकर बताया जा रहा है कि फ़लाँ भाई तनमन से पानी की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। मेयर नदारद है। मेयर का कहीं कोई बयान नहीं आता कि प्यासे शहर की आग बुझाने का उन्होंने क्या इंतज़ाम किया है। फ़िलहाल हर मर्ज़ की दवा केंद्रीय मंत्री के पुत्र देवेन्द्र चौधरी को बताया जा रहा है।

लोग सोशल मीडिया पर फ़रीदाबाद के जल संकट को लेकर तीखी टिप्पणियाँ कर रहे हैं। कुछ ने अपने अपने आरडब्ल्यूए का मज़ाक़ भी उड़ाया है जो भाजपा नेताओं की चमचागीरी में जुटे हुए हैं।

मैं, मेरी सोसाइटी मैक्सिन माफिया को जानते तक नहीं: नवीन

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: ग्रेटर फरीदाबाद के ओजोन पार्क में रहने वाले नवीन चिटकारा ने मजदूर मोर्चा के पिछले अंक (4-10 जुलाई 2021) में प्रकाशित खबर 'मैक्सिन माफिया के शिकंजे में ग्रेटर फरीदाबाद' पर कुछ तथ्य और अपनी बात पेश की है। मजदूर मोर्चा ने पीड़ित नवीन चितकारा से इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। जिससे उनका परिवार एवं तमाम सोसाइटी के निवासी आहत हुए हैं। इस संबंध में मजदूर मोर्चा ने भी अपने तौर पर तमाम तथ्यों की जानकारी हासिल की है। ओजोन पार्क सोसाइटी में गुटबाजी की वजह से नवीन चितकारा के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। नवीन चितकारा एक सीधी साधी छवि के व्यक्ति हैं और पिछले चार वर्षों से इस सोसाइटी की किसी भी कमेटी में नहीं हैं। वह चंद (2-3) महीने के लिए आरडब्ल्यूए में थे। इस दौरान उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। एक मल्टीनैशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करने वाले नवीन चितकारा न तो सोसाइटी में और न ही बाहर कोई बिजनेस करते हैं। वह कंपनी के काम से विदेश जाते

नवीन चितकारा

हैं और विदेश जाना गलत कैसे हो सकता है। उनकी पत्नी एक सरकारी बैंक में कार्यरत हैं।

पीएम केयर्स फंड के बारे में नवीन चितकारा का कहना है कि सोसाइटी में 8255/- (अष्टमी व रामनवमी को) रुपये जमा हुए थे, जिसे उनसे आग्रह करने पर उन्होंने कोरोना काल में सहायता के तौर पर बैंक के पीएम केयर फंड में जमा करा दिया था। उस समय भी कुछ अराजक तत्वों ने इसका विरोध किया था। नवीन चितकारा का कहना है कि कुछ

● सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा कि उन्हें बदनाम करने वाले खुद आरोपों में घिरे

लोग सोसाइटी में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं और वो अपनी इस चाल में फिलहाल कामयाब भी हो रहे है। ऐसे लोगों के मारपीट के वीडियो फुटेज मौजूद हैं। नवीन ने कहा कि "मैक्सिन माफिया" क्या होता है, इसके बारे में वो या सोसाइटी के बाकी लोग जानते तक नहीं हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान रहने की सख्त जरूरत है जो दूसरों के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पूरा ग्रेटर फरीदाबाद इन लोगों की इन्ही हरकतों की वजह से परेशान है।

मजदूर मोर्चा के उपरोक्त खबर की जांच-पड़ताल की सराहना करते हुए नवीन चितकारा ने बताया कि कुछ संकीर्ण सोच की प्रवृत्ति के व्यक्ति समाज में उस दीमक के समान हैं जो समाज की एकता और अखंडता के खिलाफ किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे।

पुलिस फार्म हाउस मालिकों...

पेज एक का शेष

है - यह जमीन अवतार सिंह भड़ाना की है। अवतार कई बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। अब किस पार्टी में हैं, कोई नहीं जानता। इसी तरह उनके सगे भाई और भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना की भी अरावली जोन में असंख्य प्रॉपर्टी है। अवतार और करतार चूंकि खासे बदनाम हैं, इसलिए उनका नाम इस मामले में बार-बार आता है लेकिन अब तो भाजपा के तमाम बड़े नेताओं, केंद्रीय मंत्री, सांसदों की प्रॉपर्टी अरावली जोन में है। पीएलपीए लैंड पर होने की वजह से एमसीएफ इन्हें अवैध मानता है। इनके अलावा बिजली बोर्ड, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरों की भी प्रॉपर्टी अरावली में पीएलपीए लैंड पर है।

बेईमान जिन्दाबाद

अरावली जोन में बड़े रसूखदारों के फार्म हाउस रातोंरात नहीं खड़े हुए। पूर्व कमिश्नर मोहम्मद शाइन ने जो 2018 में जो सर्वे कराया था, उसमें 60 से ज्यादा संपत्तियां मिली थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा इस सर्वे से यह हुआ था कि 5 फार्म हाउसों के सीएलयू के लिए एलओआई (सशर्त अनुमति पत्र) भी जारी कर दिया गया था। जैसे ही यह मामला पकड़ा गया, मोहम्मद शाइन ने उन पांचों एलओआई को रद्द कर दिया। इस गंदी हरकत को करने वाले सीनियर टाउन प्लानर सतीश पाराशर को मोहम्मद शाइन की रिपोर्ट पर हरियाणा सरकार ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन सतीश पाराशर की इस हरकत से नगर निगम फरीदाबाद को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन विडम्बना देखिए उसी सतीश पाराशर को अब पूरे हरियाणा का मुख्य टाउन प्लानर 20 मई 2021 को नियुक्त कर दिया गया है। सोचिए जिस शख्स के खिलाफ फरीदाबाद में इतना बड़ा मामला हुआ हो, उसे पूरे हरियाणा की कमान दे दी गई। हरियाणा का चीफ टाउन प्लानर अपने फरीदाबाद कार्यकाल के कारनामों को छिपाने में जोर नहीं लगाएगा, कौन ऐसा दावा कर सकता है। मजदूर मोर्चा सतीश पाराशर की नियुक्ति पर विस्तार से छाप चुका है।

पूर्व कमिश्नर शाइन ने अरावली में बसे अनंगपुर गांव के रकबे में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के सर्वे की जिम्मेदारी एमसीएफ के तत्कालीन 10वीं पास डीटीपी महिपाल सिंह व अन्य को दी थी। इन लोगों ने अपने हिसाब से सर्वे रिपोर्ट तैयार की। अवैध कब्जाधारियों के कुछ ही नाम सामने आए। कई लोगों द्वारा बनाए गए फार्म हाउस की बात महिपाल सिंह एंड मंडली ने छिपा ली। तहसीलदारों से मिलीभगत कर रजिस्ट्रियां भी करा ली गईं। विडम्बना देखिए कि वही महिपाल दो साल पहले रिटायर हो चुका है लेकिन राजनीतिक रसूख और धनबल से एमसीएफ में जमा हुआ है। उसके विभाग वालों को हर फाइल का हिसाब महिपाल को देना होता है।

अफसरों में तालमेल नहीं

फरीदाबाद में डीसी और कमिश्नर अपनी-अपनी पावर को लेकर बहुत आत्ममुग्ध और ईगो में रहते हैं। तत्कालीन कमिश्नर मोहम्मद शाइन ने तत्कालीन डीसी को सर्वे रिपोर्ट देने के साथ ही पत्र लिखकर जमीन का रिकॉर्ड देने की मांग की। उस रिपोर्ट की एक-एक कॉपी एडीशनल चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू के फाइनेंशियल कमिश्नर, डिवीजनल कमिश्नर, लैंड रिकॉर्ड के डायरेक्टर को भी उस समय उन्होंने भेजी थी। डीसी फरीदाबाद ने वो रेकॉर्ड कभी भी एमसीएफ को नहीं भेजा। उस समय शाइन के पत्र लिखने से कई आईएएस अफसर नाराज हुए थे। बीच में डीसी और कमिश्नर यशपाल यादव काफी समय तक दोनों पदों पर रहे। उस समय भी यह काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। इस मामले में जिला नगर वास्तुकार (डीटीपी) की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।